stipulation laid down by the world Bank for further aid to India is that the development expenditure in India should be reduced drastically ?

SHRI MORARJI DESAI : I am sorry I cannot subscribe to the intellectual exercise which the hon. Member has posed before me namely that the report is confidential but the contents are not confidential. Because somebody tries to ferret it out and publish it, I cannot be an abettor of it by either confirming or denying it.

PROHIBITION

*396. SHRI SEZHIYAN: Will the Minister of SOCIAL WELFARE be pleased to state:

(a) the progress made so far in implementing prohibition in the country;

(b) the steps taken by Government to intensify and extend the prohibition scheme in the country; and

(c) the plan and the targets for the year 1968-69 set by Government in this regard?

THE MINISTER OF STATE IN THE DEPARTMENT OF SOCIAL WELFARE (SHRIMATI PHULRENU GUHA) (a) to (c). Prohibition being a State Subject, the Union Government has no primary responsibility in directing or implementing prohibition in different States. Each State Government is within its rights to pursue its own policy. It is outside the purview of the Union Government to make any plans and to fix any targets for implementation of prohibition in different States. The Union Government continue to puruse the policy laid down in the Constitution and have made provision of Rs. 2 lakhs for giving grants for educational work on prohibition.

SHRI SEZHIYAN: Prohibition has, definitely been enjoined on the State as a Directive Principle in the Constitution and therein it has been specifically stated that the States shall endeavour to bring about prohibition.....

AN HON. MEMBER : It is only 'endeavour'.

SHRI K. LAKKAPPA: It is a violation of the Directive Principles of the Constitution.

SHRI SEZHIYAN: Article 47 provides that:

....the State shall endeavour to bring about prohibition.....

The definition of the term 'State' has been clearly given in article 12 in Part III of the Constitution and it includes Parliament and the Union Government. Therefore, the hon. Minister here cannot escape from the responsibility enjoined by the Constitution. In view of the definite directive given here and also the definition of the term 'State', may I know from the hon. Minister what endeavour have been made by the Central Government not only to improve prohibition but also to prevent their own congress Governments in the States from scrapping prohibition ?

THE DEPUTY PRIME MINISTER AND MINISTER OF FINANCE (SHRI MORARJI DESAI): The term 'State' includes the Union Government and Parliament, as hon. Member has said, but it also includes the State Government and the State Legislatures....

SHRI S. KANDAPPAN: What has he done about it ?

SHRI MORARJI DESAI: And definite powers have been allocated to the States as well as the Union Governments.

The subjects of prohibition has been allotted to the State Governments.

SHRI SEZHIYAN: What have the Central Government done to implement this policy ?

SHRI SONAVANE: Why should the hon. Member object to the adoption of Hindi for the official language when it is enshired in the Constitution ?

SHORT NOTICE QUESTION

COMPLAINTS RE. HIGH TELEPHONE BILLS

S.N.Q. 3. SHRI S. K. TAPURIAH: Will the Minister of COMMUNICATIONS be pleased to state:

(a) Whether numerous complaints have been received from Members of Parliament and others for unduly high telephone bills much above their average during the last several months;

(b) if so, whether, investigations into these complaints have been made; and

(c) if so, the result thereof ?

THE MINISTER OF PARLIAMENTARY AFFAIRS AND COMMUNICATIONS (DR. RAM SUBHAG SINGH): (a) A number of complaints against over-billing are received.

(b) Yes, Sir.

(c) The bills are corrected, where necessary

SHRI S. K. TAPURIAH: The results of the working of the Telephone Department the Posts and Telegraphs Department and the Railways etc.very clearly reflect the fact that in spite of Government's avowed policy of socialism, they have very miserably failed the people in regard to the working of these public utility projects. The grievances of the subscribers increase almost in the same ratio as the rise in tariff. Therefore, may I know the average number of complaints received monthly regarding overbilling for the last two years, and the mechanism that the Department has for verification of these complaints, that is to say, how they verify the complaints, whether there is any instrument to check whether there has been over-counting in meters, and how they keep a watch on the complaints received ?

DR. RAM SUBHAG SINGH: I do accept his thesis that the work is deteriorating. We issue about 6 lakh bills. In Delhi, the rental bills issued per month come to about 22,000. The number of complaints is about 4 to 5 per thousand, and from Members of Parliament it is about 2 to 3. The position has improved remarkably during the past three or four months.

SHRI S. K. TAPURIAH: I wanted to know the number of complaints:

DR. RAM SUBHAG SINGH: I have already given the number.

SHRI S. K. TAPURIAH: The increase in the rates in the Posts and Telegraphs Department, the Telephone Department and the losses in the railways very clearly show that their working is not satisfactory. If in spit of that the hon. Minister says that it is satisfactory, then let him have that satisfaction. I do not think I should ask of him another question.

श्री प्रेम चन्द वर्मा : क्या सरकार किसी ऐसी योजना पर गौर कर रही है कि टेलीफोन बिलों का निश्चित अवधि के अन्दर अगर पेमैंट कर दिया जाय तो उस के ऊपर लोगों को रिबेट दिया जाय, यदि हां, तो किस हिसाब से यह रिबेट देने की योजना है और कब तक इस की घोषणा कर दी जाएगी ?

डा० राम सुभग सिंह : माननीय सदस्य ने बड़ा अच्छा सवाल किया है। अब तक लोगों का टेलीफोन बिलों के पेमैन्ट पर कोई रिबेट नहीं दिया जाता था लेकिन अब पहली अप्रैल से हम एक योजना चालू कर रहे हैं जिसमें प्रति बिल पर चार रुपए का रिबेट दिया जायगा ?

श्री कंवर लाल गुप्त : तीन, चार महीने पहले दिल्ली में यह जो टेलीफोन डाइरैक्टरी निकली थी तो जनरल मैनेजर ने डाइरैक्टरी में बहुत सारी चीजें लिखी थीं कि यह-यह चीजें टेलीफोन डिपार्टमैन्ट करेगा लेकिन क्या यह सही है कि उस में से एक तिहाई चीज भी अभी तक पूरी नहीं हुई है, यदि हां तो क्या-क्या चीज पूरी नहीं हुई है और उन के पूरा न हो पाने के क्या-क्या कारण हैं और यह कि वह कब तक पूरी हो जायेंगी ?

डा० राम सुभग सिंह : जितनी बातों की वहां पर चर्चा की गई थी कि इन-इन चीजों को किया जायगा तो उस के लिए समय भी निर्धारित किया गया था कि कब तक वह-वह चीजें पूरी की जाएंगी, कितने दिनों के अन्दर उन सारे कार्यों की क्रियान्वित होगी। अब अगर प्रश्नकर्ता महोदय समझते हैं कि किसी कार्य को निश्चित समय के अन्दर क्रियान्वित नहीं हुई तो उसे वह बतला सकते हैं कि और मैं उस बारे में उनको बतलाऊंगा।

श्री हुकम चन्द कछवाय : जो मन्त्री महोदय को बहुत सी शिकायतें मिली हैं उन में उन्हें क्या इस प्रकार की भी शिकायत मिली है कि जो डाइरैक्टरी छपती है वह अंग्रेजी में छपती है और वह हिन्दी में नहीं छपती है तो मैं जानना चाहता हूं कि वह हिन्दी में कब तक छपने लगेगी ?

डा० राम सुभग सिंह : मध्य प्रदेश, राजस्थान, बिहार और उत्तर प्रदेश में हिन्दी की डाइरैक्टरी छप गयी है। दिल्ली में भी हिन्दी की डाइरैक्टरी छप रही है।

श्री रामसेवक यादव : मैं संचार मन्त्री को धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने बिहार आदि राज्यों में टेलीफोन डाइरैक्टरी हिन्दी में छपवायी है लेकिन आखिर उत्तर प्रदेश ने क्या कसूर किया है जो वहां अभी तक ऐसा नहीं किया गया है ?

डा० राम सुभग सिंह : अब उत्तर प्रदेश माननीय सदस्य का प्रदेश है और वह इस में देरी लगने का कारण बखूबी समझ सकते हैं। वहां पर इधर, उधर आन्दोलन होते रहने के कारण ऐसा हुआ है बहरहाल वहां पर भी हम लोग उसे हिन्दी में छापने का काम कर चुके हैं और वहां भी हिन्दी की डाइरैक्टरी आ रही है।

श्री शिव नारायण : आपने कई शहरों के बीच यह डाइरैक्ट टैलीफोन डायल सिस्टम तो कर दिया है लेकिन यहां से लखनऊ तक हमें टेलीफोन पर लाइन मिलाने में 2, 2 घन्टे लग जाते हैं तो इस देरी को कम करने के लिए वह क्या प्रबन्ध करने जा रहे हैं ? दूसरी बात यह है कि टेलीफोन आप करें और पैसा हम से चार्ज हो जाए तो इसको ठीक करने के लिए भी आप ने क्या कोई इंतजाम किया है ?

डा० राम सुभग सिंह : हो सकता है कि माननीय सदस्य को ऐसी दिक्कत अनुभव हुई हो बाकी मैं आगे के लिए उनसे वायदा करता हूं कि उन्हें इस तरह से इतनी देर नहीं लगा करेगी और जब उन्हें डाइरैक्ट मिलाने की जरूरत पेश आएगी तो उन्हें लाइन तत्काल मिल जाया करेगी। दूसरे अधिक पैसा उन से चार्ज होने की जो बात है उस के लिए मैं उनके टेलीफोन बिल की दुरुस्ती वगैरह करवा दूंगा ताकि उनको बिल में जरूरत से अधिक रुपया न देना पड़े।

SHRI S. K. TAPURIAH: Why this discrimination between Shri Sheo Narain and other members ?

श्री राम चरण : जब हम खुर्जे से ट्रंक-कौल करते हैं तो लाइन कटी हुई या खराब मिलती है। हालत यह है कि दिन को वह ठीक होती है लेकिन शाम को वह खराब हो जाती है। रात में तांबे के तार काट लिये जाते हैं और उन की जगह फिर दिन में लोहे के तार लगाये जाते हैं और इस तरह लाइन चालू हो जाती है। क्या सरकार मेरे क्षेत्र में लगे हुए तांबे के तार को हटा कर उसकी जगह अल्यूमीनियम की तार लगाने जा रही है जिससे यह आये दिन डिस्कनैक्शन न हुआ करे ?

डा० राम सुभग सिंह : मैं आप के माध्यम से माननीय सदस्य से निवेदन करूंगा कि वह अपने यहां के लोगों में थोड़ा क़ानून को पालने की प्रवृत्ति बढ़ायें ताकि इस तरह से टेलीफोन लाइनों के तार न काटे जाया करें। सरकार भी इस विषय में विशेष सतर्कता बर्त रही है और साथ ही एक विशेष प्रकार के लोहे के तार जिन पर तांबा मढ़ा होगा वह लगाने की व्यवस्था की जा रही है।

SHRI CHENGALRAYA NAIDU: Is it a fact that due to the inefficiency and indifference of the telephone exchange in Delhi the public are not booking calls now and the income has gone down, and to make up the income they are including ghost calls in the subscribers' bills and charging more ?

DR. RAM SUBHAG SINGH: The income has not gone down. We will check up if there is any particular difficulty which the hon. member has been experiencing and I will see that that is rectified.

श्री मीठा लाल मीना : बयाना और आगरा के बीच होने वाली टेलीफोन के तारों की चोरियों के बारे में मेरे एक प्रश्न के उत्तर में मन्त्री महोदय द्वारा बतलाया गया था कि सन् 1966–67 में 5000 रुपए की लागत की चोरी हुई और 1967–68 में 13000 रुपए

की लागत की चोरी हुई लेकिन एक भी चोर पकड़ में नहीं आया। मैं मन्त्री महोदय से जानना चाहता हूं कि इस प्रकार से जो हानि होती है और चोर पकड़ में नहीं आते हैं तो उस के लिए क्या वह कोई सक्रिय कदम उठाने जा रहे हैं ?

डा० राम सुभग सिंह : माननीय सदस्य का सवाल बड़े महत्व का है बाकी मैं उनको बतलाना चाहूंगा कि यह चोरी को पकड़ने का काम उन के प्रतिनिधियों का है जोकि राज्यों में हैं। हम लोग चोर नहीं पकड़ते हैं हम लोग तो यह टेलीफोन के तार लगाते हैं। अब यह जो टेलीफोन के तारों की चोरियां हुआ करती हैं तो उन को पकड़ने की जिम्मेदारी सम्बन्धित राज्य सरकारों की है। हम ने राज्यों के मुख्य मन्त्रियों को लिखा है कि वह इस बारे में अपने यहां की पुलिस को सतर्क करें और उन लोगों ने इस बारे में सतर्कता बर्तने की व्यवस्था भी की है और हम भी यहां से उस के लिए कोशिश करेंगे।

SHRI SONAVANE: There is a lot of delay in putting up bills for the trunk calls. So, may I know what steps will be taken to see that bills are immediately put up, within a week or so, so that the subscribers are not put to unnecessary difficulty and immediate payment can be made to the department ?

DR. RAM SUBHAG SINGH: Actually, the House would feel satisfied that we have introduced a new method. That was done only recently. Two types of bills are there. On the 11th of every month say the subscriber gets his trunk call bill. This is the form in which the new bill has been introduced. On the 11th of every third month the subscriber gets another bill. That gives the details of rentals, general calls etc. These bills contain all the dues of the subscriber. We have also given a telephone number there and said that if they find any irregularity, they may kindly telephone that particular number. Now, the complaints have gone down quite a lot.

SHRI S. M. BANERJEE: May I know whether it is a fact that there was a proposal that those subscribers who pay their bills in time will be given some rebate ? That was the proposal in the last council meeting. May I know what has happened to that proposal?

DR. RAM SUBHAG SINGH: I have already said in reply to Shri P. C. Varma that we are going to give a rebate of Rs 4/- on every bill from 1st April.

श्री य० द० शर्मा : जैसा मन्त्री महोदय जानते हैं, टेलीफोन आज की अत्यन्त आवश्यक सुविधा है। तो क्या टेलीफोन विभाग के सामने कोई इस प्रकार की योजना है कि देश के दूरवर्ती कटे हुए क्षेत्रों को बाकी के साथ जोड़ने के लिए बिना मुनाफेबाजी का ध्यान रखे हुए, शीघ्र प्रयत्न किया जाये ?

डा० राम सुभग सिंह : योजना अवश्य है, माननीय सदस्य के इलाके में थोड़ी दिक्कत है इस को मैं जानता हूं। लेकिन यह टेलीफोन व्यवस्था उन दूरवर्ती इलाकों को उपलब्ध करने की योजना है जो कम-से-कम तहसील हो और जहां की आबादी चार या पांच हजार से ज्यादा हो। अगर वहां के लोग टेलीफोन लेने को तैयार होंगे तो हम वहां यह सुविधा प्रदान करने का प्रयत्न अवश्य करेंगे। एक दिक्कत है कि को-एक्सिअल केबल यहां उतना नहीं बनता है जितनी मात्रा में उस की आवश्यकता है। इसलिए हम को उसे इम्पोर्ट करना पड़ता है। कापर वायर को भी इम्पोर्ट करने की जरूरत है। जहां इम्पोर्ट वाली बात आती है वहां थोड़ी कठिनाई हो जाती है। इस लिए दूरवर्ती इलाकों को मिलाने और इम्पोर्ट घटाने दोनों को जोड़ कर एक समन्वित नीति हम लोग तुरन्त चालू करेंगे।

SHRI HEM BARUA: The Posts & Telegraphs Department is one of the most incompetent departments of the Government and the conditions in the telephone department are most chaotic. One day, Sir, I went to the exchange here to book a trunk call to Gauhati, Assam. The operator told me that Assam is not part of India. In this context, may I know (a) whether Government are going to educate the operators on the geography of India and (b) whether Government are going to pinpoint their attention to find out the loopholes and plug them in the interest of the public ?

DR. RAM SUBHAG SINGH: I might be excused if I say that my hon. friend, Shri

Hem Barua, has developed this habit of denouncing over 6 lakh employees of the telephone department due to the lack of his experience. Nobody can say that the entire Parliament is wrong if Mr. Barua fails to understand anything. Similarly, based on the experience of one man, he should not generalise that the entire department is incompetent, as he is doing. There may be some person in our country who may not understand, but I can tell him emphatically there is no employee in the postal department who is charged with this work who does not know where Assam is.

SHRI HEM BARUA: Sir, the hon. minister has tried to be very personal in his reply. Does he mean to say that I told you a lie when I said that the telephone operator here did not know where Assam is ?

DR. RAM SUBHAG SINGH: He could have easily written to me about it and I could have enquired about it. But he does not realise his primary responsibility.

SHRI S. R. DAMANI: There are many sections where if calls are booked, we are always informed that the lines are out of order. For days and days the lines are not working. May I know whether the attention of the Minister has been drawn to this matter and what steps have been taken to improve these lines so that they may work ?

DR. RAM SUBHAG SINGH : That is true, because in certain places where the wire is cut or stolen this type of difficulty does arise. All the far-flung areas like Srinagar, Jammu, Jorhat, Tinsukia, Imphal, Kohima etc., are going to be connected by micro-wave links. We are also going to connect all other important areas by co-exial links. Also in Bombay we are setting up an automatic trunk centre wherefrom most of the important areas will be connected. By these measures I hope the difficulties will be reduced greatly.

श्री रघुवीर सिंह शास्त्री : मैं मन्त्री महोदय से जानना चाहता हूं कि क्या उन को पता है कि गांवों से जब टेलीफोन लेने के लिए प्रार्थना पत्र आते हैं तब उन पर समुचित ध्यान नहीं दिया जाता ? यदि यह ठीक है, तो क्या मन्त्री महोदय गांवों के प्रति बढ़ती जा रही उपेक्षा को दूर करने का आश्वासन देंगे ?

डा० राम सुभग सिंह : गांवों का ही यह देश है और गांवों के प्रति हम अपनी पूरी जिम्मेदारी निभाएंगे । यदि श्री शास्त्री गांवों का कोई उदाहरण हमें देंगे तो हम तुरन्त उस की देख रेख करेंगे ।

SHRI JYOTIRMOY BASU: Since it is a fact that from the date you have brought in machine-accounting errors in the bills are numerous—you have been exaggerating bills and at the same time you have been understating bills—could you tell us in how many places you have installed machine-accounting in preparing telephone bills?

DR. RAM SUBHAG SINGH: Actually, as my hon. friend may be aware, it is there only in Calcutta. We wanted to introduce it here. In Calcutta the position has improved due to introduction of the computer system. Here also the condition is improving with a little better attention. I must, in this connection, appreciate our people who are working here in Delhi. Their functioning has improved. I am sure within a very short time there will be noticeable improvement. I may also say that any complaint from any area, if the hon. Member brings it to our notice, will be expeditiously attended to.

SHRI JYOTIRMOY BASU: Since the time you have machine-accounting in Calcutta the bills have been highly exaggerated..

MR. SPEAKER: The hon. Minister has said that he will look into it.

श्री ओ० प्र० त्यागी : क्या सरकार का ध्यान इस ओर आकर्षित हुआ है कि टेलीफोन देने में प्रार्थना-पत्र की योजना पर ध्यान न दे कर टेलीफोन डिपार्टमैन्ट के लोग रिश्वत ले कर टेलीफोन कनेक्शन दे रहे हैं ? क्या खास तौर से मुरादाबाद क्षेत्र से आप के पास कोई ऐसी शिकायत पहुंची है । अगर पहुंची है तो उस सम्बन्ध में क्या एन्क्वायरी की गई है ? की गई है तो उस का परिणाम क्या निकला है ?

डा० राम सुभग सिंह : अगर कोई ऐसी शिकायत है तो उस को जनरलाइज करने के बदले मनानीय सदस्य हम को बतलायें और हम इस की जांच करायेंगे । लेकिन मैं यह नहीं

मानता कि मुरादाबाद में अगर कोई गलती हुई है तो वह सारे भारत में हुई है। माननीय सदस्य ने कुछ इसी रूप में कहा। अगर वह हम को मुरादाबाद के बारे में बता दें तो हम उस की जांच करायेंगे और जिस की भी गलती होगी उस के खिलाफ ऐक्शन लिया जायेगा।

श्री शिवचंडिका प्रसाद : मैं जानना चाहता हूं कि क्या यह बात सही है कि जिन कैंडिडेट्स ने गत चुनाव के समय में स्पेशल टेलीफोन लाइन प्राप्त करने के लिए सिक्योरटी डिपाजिट किया था, उन को वह रुपए साल भर के बाद भी अभी तक लौटाए नहीं गए हैं ?

डा० राम सुभग सिंह : अगर माननीय सदस्य श्री शिवचंडिका प्रसाद का रुपया नहीं लौटा तो वह अपना आवेदन पत्र भेज दें, मैं उस को तत्काल लौटवा दूंगा। लेकिन हम को यह पता नहीं है कि उन का आवेदन पत्र आया भी है या नहीं।

श्री महन्त दिग्विजय नाथ: मैं माननीय मन्त्री महोदय को यह बतलाना चाहता हूं कि ऐसे भी लोगों के पास ट्रंक काल के बिल भेजे गए हैं जिन्होंने ट्रंक काल किया ही नहीं है। उदाहरण के लिए माननीय सदस्य श्री आत्म दास के पास 35 रु० का बिल आया है लेकिन उन्होंने एक भी ट्रंक काल नहीं किया।

डा० राम सुभग सिंह : मैं महन्तजी की बातों को मानता हूं। अगर ऐसा कोई भी बिल गया है तो मैं उस को वापस कराऊंगा। लेकिन मैं अपना उदाहरण देता हूं कि मैं तो दिन भर घर से बाहर रहता हूं लेकिन मेरे यहां कई ऐसे मेहमान या दूसरे लोग होते हैं जो कि ट्रंक-काल करते हैं। उन से पैसे मांगने वाला कोई नहीं है। वह बिल हमारे यहां आते हैं और हम को ही पैसे देने होते हैं।

SHRI PILOO MODY: My hon. friend, Shri Hem Barua, has stated rather dramatically that the operator does not know where Assam is. May be, in this particular case it happened; but it has happened to me and my friends a great many times when the operator does not know where a particular place is, and very often they go to the extent of asking you through what exchange the call is cleared. Therefore, I am suggesting to the hon. Minister that it may be worthwhile if the telephone operators are given some sort of lesson in geography, or at least a geography of the telephone system to avoid complaints of this type.

MR. SPEAKER: It is good suggestion.

WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

LIQUOR IN COCA-COLA BOTTLES

*397. SHRI K. ANIRUDHAN:
SHRI VISWANATHA MENON:
SHRI K. RAMANI:

Will the Minister of SOCIAL WELFARE be pleased to state:

(a) whether the attention of Government has been drawn to the news-item published in the Indian Express of the 3rd January, 1968 that in hotels and restaurants in Delhi, liquor is served in Coca-Cola bottles;

(b) whether Government have investigated into the matter; and

(c) If so, the findings thereof and the action taken thereon ?

THE MINISTER OF STATE IN THE DEPARTMENT OF SOCIAL WELFARE (SHRIMATI PHULRENU GUHA) (a) and (b). Yes, Sir.

(c) A copy of the Report of the Inquiry Committee is laid on the Table of the House [*Placed in Library. See.* No. LT—301/168]. The recommendations of the Committee regarding defaulting licensees have been implemented.

HARIJANS IN MADHYA PRADESH

*398. SHRI P. C. ADICHAN:
SHRI R. BARUA:

Will the Minister of SOCIAL WELFARE be pleased to state:

(a) whether Government's attention has been drawn to the reports of wide-spread atrocities on Harijans in certain parts of Madhya Pradesh especially in the Gwalior region of the State;

(b) whether Government have made any Investigation into these reports;

(c) If so, with what results; and